



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128858

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 15793/2026

विशाल गौतम उर्फ टोनीआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मनीष कुमार सिंह, श्याम मोहन सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अनुराग दुबे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. सूचक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, पुलिस स्टेशन सिकरारा, जिला जौनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 112/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं धारा 319(2), 318(4), 109(1), 308(5), 127(2), 61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक नामजद नहीं है, यद्यपि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, नामतः पवन यादव को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा प्रकीर्ण आपराधिक जमानत आवेदन संख्या- 2026 का 14918 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के पैरा संख्या 23 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है और वह 25.03.2026 से जेल में बंद है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, नामतः पवन यादव को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, नामतः पवन यादव को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उस पर रोक लगाई गई है, तथा आवेदक 25.03.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- विशाल गौतम उर्फ टोनी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।
 - (ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
 - (iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।
 - (iv) आवेदक वाद को शुरू करने, आरोप विरचित करने और सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

नितेंद्र

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"